(b) whether it is also a fact that the various Kisan Sabhas have demanded a minimum statutory price for sugarcane between Rs. 30/- and Rs. 35/- per quintal; and

(c) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) Yes, Sir. The Central Government have announced that the statutory minimum price of sugarcane payable by sugar factories for the 1987-88 season will be fixed at Rs. 18.00 per quintal, linked to a basic recovery of 8.5 per cent with proportionate premium for higher recoveries.

(b) and (c) The Central Government has not received any representation from Kisan Sabhas demanding the raise of the statutory minimum price of Rs. 18 to Rs. 30 to Rs. 35 per quintal.

कृषि विश्वविद्यालयों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए स्थानों का आरक्षण

2487. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि विश्व-विद्यालयों में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपने पास उपलब्ध स्थानों के कोटे से विभिन्न राज्य सरकारों को स्थान आबन्टित करते समय मनमानी की है तथा किसानों के बच्चों और बिहार के छात्रों की उपेक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी नहीं श्रीमान् । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि डिग्री कार्यक्रमों के लिये परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार बिहार सहित विभिन्न राज्यों को सीटें आबंटित करती रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुनर्वास कालोनियां

2488. **श्री शरद यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1986 के हिन्दुस्तान (हिंदी संस्करण) में "दो मुल्लाओं की लड़ाई में पुनर्वास कालोनियां फंसी" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) पिछले आठ महीनों में उस इलाके में स्टाफ पर खर्च की गई राशि के अलावा नागरिक सुविधाओं के लिए कितना धन खर्च किया गया है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले आठ महीनों के दौरान उस इलाके में नागरिक सुविधाओं में कटौती की है ; और

(घ) दस लाख की आबादी वाले उस इलाके में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 313.35 लाख रुपये ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण पहले ही नागरिक सुविधाएं मुहैया कर रहा है ।

Selling of food stuff at higher rates

2489. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some of the States are supplying food stuffs to the Tribal people at higher rate than fixed by the Central Government; if so, the names of such States; and

(b) what action has been taken to stop such practice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD):